राज्य कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी, 34 करोड़ रुपये खर्च होंगे

निजी वाहन चालकों के लिए कल्याण योजना

Join VacancyBihar.in > (Whatsapp Channel)

फैसला 1

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के निजी वाहन चालकों को भी बीमा, मेडिकल जांच समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने निजी वाहन चालकों के लिए कल्याण योजना के प्रस्ताव पर सहमति दी। बैठक में 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य से निर्गत लाइसेंस धारक वाहन चालकों व उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक उन्नयन और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना है।

इस योजना के तहत ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी समेत अन्य निजी वाहन चालकों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके पश्चात उन्हें यूआईडी मिलेगा। इसके बाद उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। वाहन चालकों को प्रशिक्षण, चिकित्सीय सुविधा, बीमा, श्रम संसाधन से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनकी मेडिकल जांच भी की जाएगी। पढ़िए राजकाज

राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 11 नवंबर से

कल्याण योजना की खास बातें

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर जांच
- नेत्र जांच
- भारी वाहन चालक प्रशिक्षण
- चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण
- चालक पोशाक

और क्या: इस योजना पर 34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत सभी 38 जिलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। प्रारंभिक लक्ष्य डेढ़ लाख लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंचाने का है

45 एजेंडों पर मिली सहमति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में

कक्षपालों को साल में 13 माह का वेतन

2 बिहार राज्य की काराओं के कक्षपाल संवर्ग के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय मिलेगा। इस तरह उन्हें 13 माह का वेतन अनुमान्य होगा। इसका लाभ कक्षपाल, उच्च कक्षपाल एवं मुख्य उच्च कक्षपाल को मिलेगा।

हॉकी चैंपियनशिप के लिए 10 करोड़ मंजूर

राजगीर में 11-20 नवंबर को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप **3** का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी। इसके लिए हाकी इंडिया को 10 करोड़ की धनराशि दी गयी है। साथ ही बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक को हॉकी इंडिया के साथ एमओयू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पिछले 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में राज्य खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय के उद्घाटन किया था। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष-सचिव ने राजगीर में इस चैंपियनशिप के आयोजन का प्रस्ताव दिया था।

राहत: सीएनजी-पीएनजी पर वैट दरें घटीं

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कैबिनेट ने राज्य में शहरी गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति उपभोक्ता, प्रतिदिन 50 **4** हजार एससीएमडी तक की बिक्री से मामले में वैट की दरों में कमी के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। इसके तहत प्राकृतिक गैस सीएनजी व पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर पहले की अपेक्षा कम होगी। सीएनजी पर वैट की दर 20 फीसदी के स्थान पर 12.5 फीसदी जबकि पीएनजी पर 20 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी होगी।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि व्यवसाय एवं उद्योग संगठनों द्वारा अनुरोध किया गया था कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार राज्य में नेचुरल गैस पर वैट की दर अधिक है। व्यवसायिक संगठनों द्वारा यह भी बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोयला-फर्नेस ऑयल से चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित करने का निर्देश दिया है।

Join VacancyBihar.in > (Whatsapp Channel)